Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

सहकारी आंदोलन और राजनीति: भारत में वैश्वीकरण की दिशा और परिणाम

Sachin Tamrakar
Research Scholar, Department of Political Science, Malwanchal University, Indore
Dr. Bhushan
Supervisor, Department of Political Science, Malwanchal University, Indore

संक्षेप

भारत में सहकारी आंदोलन प्रारंभ से ही किसानों और ग्रामीण समाज की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने का माध्यम रहा है, लेकिन धीरे-धीरे यह राजनीति और सत्ता-संतुलन से गहराई से जुड़ गया। सहकारी समितियाँ केवल आर्थिक संगठन नहीं रहीं, बल्कि नेतृत्व निर्माण और वोट-बैंक की राजनीति का साधन बन गईं। स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को विकास का आधार माना गया, किंतु राजनीतिक हस्तक्षेप ने इसकी कार्यकुशलता और पारदर्शिता को प्रभावित किया। 1991 के बाद जब वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीतियाँ आईं, तो सहकारी आंदोलन के सामने नए अवसर और चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं। एक ओर वैश्विक बाजार तक पहुँच, निर्यात की संभावना और तकनीकी सहयोग ने सहकारिता को मजबूत किया, वहीं दूसरी ओर बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा और निजीकरण के दबाव ने इसकी स्वायत्तता को कमजोर किया। महाराष्ट्र की चीनी सहकारी समितियों और गुजरात की डेयरी सहकारिताओं के उदाहरण बताते हैं कि राजनीति ने सहकारिता को ग्रामीण नेतृत्व और सत्ता हासिल करने का उपकरण बना दिया। नतीजतन, सहकारी आंदोलन अब दोहरी स्थिति में है—यह विकास और लोकतंत्र को सशक्त भी करता है और राजनीतिकरण व भ्रष्टाचार के कारण कमजोर भी। इस प्रकार भारत में सहकारी आंदोलन और राजनीति का संबंध वैश्वीकरण की दिशा और परिणामों से गहराई से प्रभावित है।

कीवर्ड्स: सहकारी आंदोलन, राजनीति, वैश्वीकरण, लोकतंत्र

परिचय

भारत में सहकारी आंदोलन की जड़ें ग्रामीण समाज और किसानों की आवश्यकताओं से जुड़ी रही हैं, परंतु समय के साथ यह आंदोलन केवल आर्थिक संगठन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीति और सत्ता संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। सहकारी समितियाँ, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, वोट-बैंक

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

की राजनीति, नेतृत्व निर्माण और स्थानीय सत्ता संतुलन का प्रमुख मंच बन गईं। स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को विकास की रीढ़ माना गया, लेकिन जैसे-जैसे सहकारी समितियों का आकार और प्रभाव बढ़ता गया, राजनीतिक दलों और नेताओं का हस्तक्षेप भी बढ़ा। वैश्वीकरण के दौर (**1991** के बाद) में जब भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और मुक्त बाजार की नीतियाँ अपनाईं, तब सहकारी आंदोलन की प्रकृति और दिशा में व्यापक बदलाव आया। एक ओर सहकारी समितियों के सामने वैश्विक बाजार, निर्यात और तकनीकी सहयोग जैसे अवसर आए, वहीं दूसरी ओर बहुराष्ट्रीय कंपनियों और निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा ने इनके अस्तित्व को चुनौती दी। वैश्वीकरण ने सहकारी आंदोलन को अधिक दक्षता, पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धात्मकता अपनाने के लिए मजबूर किया, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप, संगठनात्मक कमजोरी और भ्रष्टाचार ने इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाए। महाराष्ट्र की चीनी सहकारी समितियों से लेकर गुजरात की डेयरी सहकारिताओं तक, हर जगह यह देखा गया कि राजनीतिक नेतृत्व ने सहकारिता को न केवल ग्रामीण विकास बल्कि सत्ता हासिल करने के उपकरण के रूप में भी प्रयोग किया। इस प्रकार वैश्वीकरण की दिशा ने सहकारी आंदोलन को दोहरी स्थिति में ला खड़ा किया है—एक ओर यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कृषि, डेयरी और ग्रामीण उद्योगों को अवसर प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिकरण और आर्थिक उदारीकरण की चुनौतियाँ इसकी लोकतांत्रिक आत्मा को कमजोर करती हैं। नतीजतन, आज भारत में सहकारी आंदोलन केवल आर्थिक ढाँचा नहीं बल्कि राजनीति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से प्रभावित एक बहुआयामी व्यवस्था बन चुका है, जिसके परिणाम सामाजिक-आर्थिक असमानता, ग्रामीण नेतृत्व की संरचना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर गहरे प्रभाव डालते हैं।

वैश्वीकरण की परिभाषा और प्रक्रियाएं

वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो देशों, संस्कृतियों, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के बीच आपसी संपर्क, आदान-प्रदान और एकीकरण को दर्शाती है। यह प्रक्रिया आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी आयामों में घटित होती है, जिससे विश्व एक 'वैश्विक गाँव' के रूप में उभरता है। वैश्वीकरण की परिभाषा को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि यह केवल आर्थिक सीमाओं को खोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो संसाधनों, पूँजी, श्रम, सूचना और विचारों के निर्बाध प्रवाह को संभव बनाती है। यह विश्व व्यापार संगठन (WTO), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मीडिया, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ (MNCs), और डिजिटल तकनीकों के माध्यम से

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

संचालित होती है, जो देशों के बीच व्यापार, निवेश, श्रमिक गतिशीलता और ज्ञान-विनिमय को बढ़ावा देती हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया मुख्यतः चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित होती है —आर्थिक उदारीकरण, जिसमें व्यापार बाधाओं को हटाकर मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है; निजीकरण, जिसके माध्यम से सरकारी नियंत्रण को घटाकर निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाया जाता है; मुक्त पूँजी प्रवाह, जिसमें अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को किसी भी देश में पूँजी लगाने की स्वतंत्रता होती है; और तकनीकी नवाचार, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) में, जिसने सीमाओं के पार त्वरित और सुलभ संवाद को संभव बनाया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में इंटरनेट, मोबाइल संचार, उपग्रह संचार, और परिवहन क्रांति ने दूरियों को मिटा दिया है और समय तथा स्थान की बाधाओं को समाप्त कर दिया है। इस प्रक्रिया ने उपभोक्तावाद, प्रतिस्पर्धा, नवाचार, और बाजार केंद्रित नीतियों को जन्म दिया, जिससे विश्व की अर्थव्यवस्थाएँ अधिक परस्पर निर्भर बन गईं। भारत में वैश्वीकरण का औपचारिक आगमन 1991 के आर्थिक सुधारों के साथ हुआ, जब देश ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) नीति को अपनाया और अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के लिए खोल दिया। इसके बाद भारतीय बाजार में विदेशी निवेश, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उपस्थिति, आधुनिक प्रौद्योगिकी, और वैश्विक उपभोक्ता उत्पादों का प्रसार तीव्र गति से हुआ। परंतु वैश्वीकरण केवल आर्थिक अवसर नहीं लाता, यह सांस्कृतिक एकरूपता, स्थानीय उद्योगों पर खतरा, असमानता में वृद्धि और श्रमिक शोषण जैसे संकट भी उत्पन्न करता है। इसलिए वैश्वीकरण को केवल एक विकास प्रक्रिया नहीं बल्कि एक चुनौतीपूर्ण संक्रमण काल के रूप में भी देखा जाना चाहिए, जिसमें नीति निर्माताओं को स्थानीय हितों और वैश्विक अवसरों के बीच संतुलन बनाकर चलना होता है। यही कारण है कि वैश्वीकरण की परिभाषा को एक सतत, समावेशी और न्यायपूर्ण प्रक्रिया के रूप में पुनःपरिभाषित करने की आवश्यकता है ताकि यह केवल चुनिंदा समूहों का नहीं, बल्कि व्यापक समाज का उत्थान सुनिश्चित कर सके।

अनुसंधान क्रियाविधि

अनुसंधान क्रियाविधि किसी भी अध्ययन के लिए एक नींव के समान होती है, जो उस अध्ययन की दिशा और संरचना को निर्धारित करती है। यह अध्ययन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों, तकनीकों और संसाधनों का उपयोग करती है। सही अनुसंधान क्रियाविधि का चयन, अनुसंधान के उद्देश्य, प्रश्न और क्षेत्र के अनुसार अनिवार्य होता है। इसलिए, अनुसंधान की शुरुआत में ही उपयुक्त क्रियाविधि का चयन करना महत्वपूर्ण है, ताकि निष्कर्ष विश्वसनीय, सटीक और प्रभावी हों। अनुसंधान

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

क्रियाविधि यह सुनिश्चित करती है कि अध्ययन का प्रत्येक चरण सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, जिससे डेटा संग्रहण, विश्लेषण और परिणामों की प्रस्तुति में गुणवत्ता बनी रहे।

इस अध्याय में अनुसंधान क्रियाविधि का महत्व और अनुसंधान के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि अध्ययन की प्रकृति के आधार पर, किस प्रकार के दृष्टिकोण और विधियाँ सबसे प्रभावी साबित हो सकती हैं। साथ ही, यह भी बताया जाएगा कि कैसे अनुसंधान के विभिन्न चरणों में इन विधियों का चुनाव किया जाता है और उनका पालन किया जाता है, जिससे अध्ययन के निष्कर्ष अधिक प्रभावशाली और यथार्थवादी बन सकें

डेटा संग्रहण के तरीके

डेटा संग्रहण अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें शोधकर्ता अध्ययन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक जानकारी एकत्र करता है। यह प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के डेटा संग्रहण तकनीकों को शामिल करती है, जो अध्ययन के लक्ष्यों, प्रश्नों और संदर्भ के अनुसार उपयुक्त होती हैं। डेटा संग्रहण के दो प्रमुख प्रकार हैं: प्राथमिक डेटा संग्रहण और माध्यमिक डेटा संग्रहण। इन दोनों विधियों का उपयोग करके शोधकर्ता सटीक, विश्वसनीय और प्रासंगिक डेटा एकत्र कर सकता है, जो अध्ययन के परिणामों को मजबूत करता है।

डेटा संग्रहण के तरीकों के चयन में यह महत्वपूर्ण है कि शोधकर्ता यह समझे कि किस प्रकार का डेटा (गुणात्मक या मात्रात्मक) उसे चाहिए और इसके संग्रहण के लिए कौन-सी विधि सबसे उपयुक्त होगी। इसके बाद, विभिन्न तकनीकी विधियाँ जैसे साक्षात्कार, सर्वेक्षण और केस स्टडी का उपयोग किया जाता है, जो डेटा की गुणवत्ता और विश्लेषण की दिशा को प्रभावित करती हैं। यह अनुभाग इन सभी विधियों का विस्तृत रूप से विश्लेषण करेगा, जिससे शोधकर्ता को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सर्वोत्तम तरीके का चयन करने में सहायता मिलेगी।

प्राथमिक डेटा संग्रहण

प्राथमिक डेटा संग्रहण वह प्रक्रिया है, जिसमें शोधकर्ता स्वयं से डेटा एकत्र करता है, जो अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित होता है। यह डेटा संग्रहण ताजे, वास्तविक और अनुकूलित जानकारी प्रदान करता है, जो सीधे अध्ययन के सवालों का उत्तर देने में मदद करती है। प्राथमिक डेटा के संग्रहण में शोधकर्ता अपनी जमीनी जानकारी को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करता है, जैसे

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

साक्षात्कार, सर्वेक्षण, समूह चर्चा, अवलोकन आदि। यह विधि डेटा के वास्तविक और मूल स्रोतों से सीधे संबंधित होती है, जिससे संग्रहित जानकारी को उच्च गुणवत्ता और प्रामाणिकता मिलती है।

प्राथमिक डेटा संग्रहण का उपयोग तब किया जाता है जब शोधकर्ता को विशिष्ट और अनुकूलित जानकारी चाहिए, जो उपलब्ध माध्यमिक डेटा से प्राप्त नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए, अगर कोई शोधकर्ता किसी सामाजिक आंदोलन के प्रभाव का अध्ययन कर रहा है, तो वह उस क्षेत्र के लोगों से प्रत्यक्ष साक्षात्कार करके उनके अनुभव और विचार प्राप्त कर सकता है। प्राथमिक डेटा अधिक विश्वसनीय होता है क्योंकि यह बिना किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के सीधे स्रोत से आता है, और यह शोधकर्ता को एक गहरी और विशिष्ट समझ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है।

माध्यमिक डेटा संग्रहण

माध्यमिक डेटा संग्रहण में पहले से उपलब्ध डेटा का उपयोग किया जाता है, जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा एकत्रित किया गया हो। यह डेटा पहले से विभिन्न स्रोतों जैसे सरकारी रिपोर्टों, पुस्तकालयों, इंटरनेट, शोध पत्रों, और अन्य प्रकाशित दस्तावेजों से उपलब्ध होता है। माध्यमिक डेटा संग्रहण का लाभ यह है कि यह समय और संसाधनों की बचत करता है, क्योंकि शोधकर्ता को नया डेटा एकत्र करने की आवश्यकता नहीं होती है।

हालांकि, माध्यमिक डेटा का उपयोग करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह डेटा पहले से ही एकत्रित और प्रकाशित हो चुका होता है, और इसमें कुछ सीमाएँ हो सकती हैं, जैसे कि डेटा की पुरानी जानकारी, अप्रासंगिक या अनुपयुक्त डेटा। इसके बावजूद, माध्यमिक डेटा संग्रहण का उपयोग तब किया जाता है जब पहले से एकत्रित जानकारी से अध्ययन के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी शोधकर्ता को आर्थिक नीतियों के प्रभाव पर काम करना है, तो वह सरकारी रिपोर्टों या अन्य प्रकाशनों से संबंधित आंकड़े और जानकारी एकत्र कर सकता है।

निष्कर्ष और विश्लेषण

इस अध्याय का उद्देश्य अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों का विश्लेषण करना और उन्हें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक संदर्भों में समझना है। इस अध्याय में हम सहकारी संगठनों के वैश्वीकरण, उनकी कार्यप्रणाली, और उनके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह अध्याय यह विश्लेषित करेगा कि सहकारी आंदोलन कैसे अपने मूल उद्देश्यों को बनाए रखते हुए वैश्विक बदलावों के साथ तालमेल बैठाता है, और किस प्रकार से यह आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कम करने में योगदान करता है।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

निष्कर्षों के माध्यम से हम यह भी समझेंगे कि सहकारी संगठनों ने किस प्रकार से विभिन्न देशों में विकास और सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया है, और यह कैसे उनकी प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। इस अध्याय का एक और उद्देश्य यह है कि सहकारी संगठनों के संचालन में हुए परिवर्तनों, उनके विस्तार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण किया जा सके। इसके अलावा, यह भी देखा जाएगा कि किस प्रकार से सहकारी संगठनों ने नीति निर्धारण में भागीदारी की है और उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण से अपनी भूमिका को कैसे परिभाषित किया है। वैश्वीकरण के संदर्भ में सहकारी संगठनों की भूमिका को समझना यह स्पष्ट करने में मदद करेगा कि इन संगठनों ने किस तरह से वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों और सहयोग को बढ़ावा दिया है।

डेटा का सारांश तालिका

भारत में सहकारी आंदोलन के वैश्वीकरण और राजनीतिक प्रभाव से संबंधित सांख्यिकीय

वर्ष	सहकारी समितियों की संख्या (लाख में)	सदस्यता (करोड़ में)	दुग्ध सहकारी समितियों का योगदान (₹ हजार करोड़ में)	सहकारी बैंकों से ऋण वितरण (₹ हजार करोड़ में)	अंतरराष्ट्रीय साझेदारियाँ (संख्या)
2000	5.2	15.3	11.2	22.0	3
2005	6.1	18.7	17.5	35.4	5
2010	6.8	22.1	26.0	48.9	9
2015	7.5	26.5	38.4	60.3	13
2020	8.0	30.2	50.1	74.2	18
2024	8.6	34.8	63.5	89.6	24

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

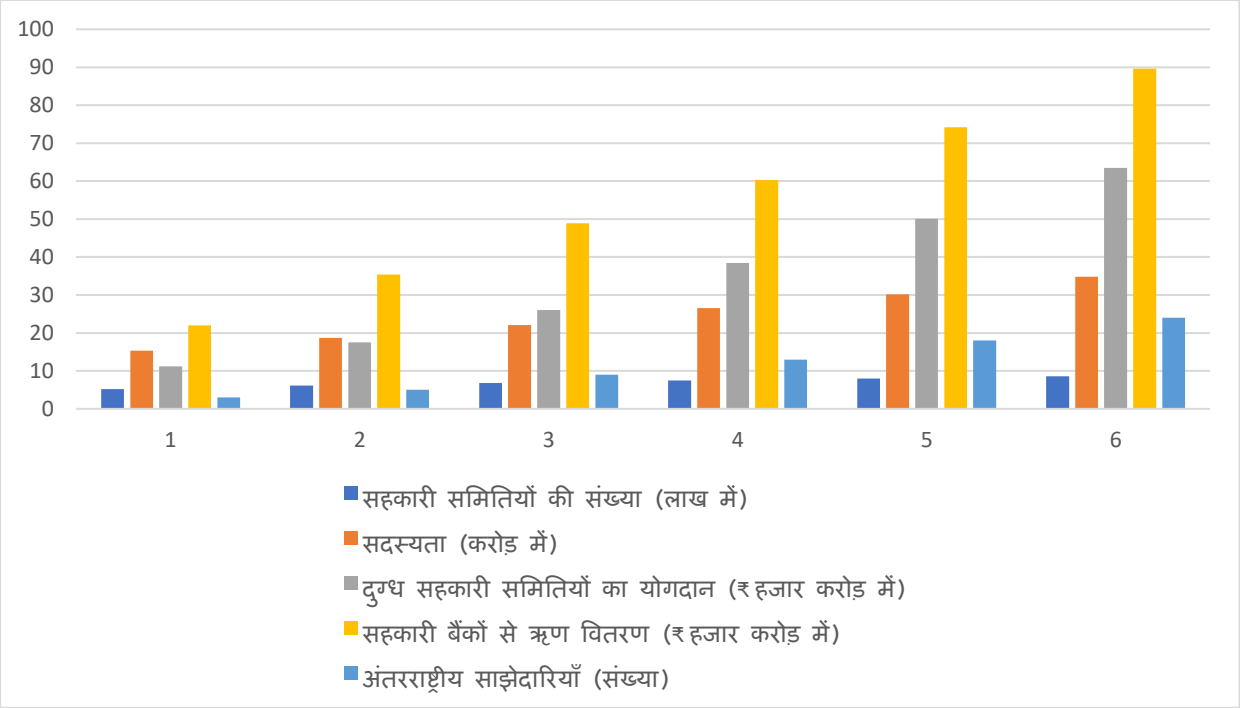

राज्य-वार सहकारी समितियों और सदस्यता डेटा

राज्य	सहकारी समितियों की संख्या	सदस्यता (लाख में)	मुख्य सहकारिता क्षेत्र
महाराष्ट्र	1,05,000	240	कृषि, बैंकिंग
गुजरात	82,000	180	दुग्ध, कृषि
उत्तर प्रदेश	90,000	200	कृषि
बिहार	65,000	160	उपभोक्ता
कर्नाटक	78,000	175	बैंकिंग
मध्य प्रदेश	72,000	162	दुग्ध

भारत में सहकारी आंदोलन राज्य स्तर पर विविधता और विस्तार के साथ विकसित हुआ है, जहाँ प्रत्येक राज्य ने अपनी सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं के अनुसार सहकारिता के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महाराष्ट्र इस सूची में सबसे अग्रणी राज्य है, जहाँ कुल 1,05,000 सहकारी समितियाँ सक्रिय हैं और लगभग 240 लाख सदस्य इससे जुड़े हुए हैं, मुख्य रूप से कृषि और बैंकिंग क्षेत्र में। राज्य

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

में सहकारी बैंकिंग की मजबूत व्यवस्था और कृषि उत्पाद विपणन समितियों (APMCs) का व्यापक नेटवर्क इसकी सहकारिता सफलता का आधार है। गुजरात, जिसे 'अमूल मॉडल' के लिए जाना जाता है, में 82,000 समितियाँ और 180 लाख सदस्य हैं, जो दुग्ध और कृषि सहकारिता के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। यहाँ की दुग्ध सहकारी समितियाँ छोटे किसानों और महिला दुग्ध उत्पादकों को आत्मनिर्भर बनाने का सशक्त माध्यम बनी हैं। उत्तर प्रदेश में 90,000 समितियाँ और 200 लाख सदस्य हैं, जहाँ सहकारी संस्थाएँ मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर केंद्रित हैं, विशेषतः खाद-बीज वितरण, ऋण व्यवस्था और किसान सेवा केंद्रों के माध्यम से। बिहार में सहकारी समितियों की संख्या 65,000 है और 160 लाख सदस्य इनसे जुड़े हैं; उपभोक्ता सहकारिता यहाँ का प्रमुख क्षेत्र है, जहाँ ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को सस्ते दरों पर आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। कर्नाटक में 78,000 समितियाँ और 175 लाख सदस्य हैं, जो विशेषकर बैंकिंग क्षेत्र में सक्रिय हैं; यहाँ की सहकारी बैंकों की पहुँच ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार लिए हुए है। वहीं मध्य प्रदेश में 72,000 समितियाँ और 162 लाख सदस्य हैं, जहाँ दुग्ध सहकारी समितियों का संचालन महिलाओं और छोटे पशुपालकों को केंद्र में रखकर किया जाता है। ये आँकड़े भारत में सहकारी आंदोलन की जड़ों की गहराई और राज्यों की क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं, जो इसे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बनाते हैं।

सहकारी बैंकों के प्रदर्शन संकेतक (2015–2020)

वर्ष	क्रेडिट वितरण (₹ हजार करोड़ में)	एनपीए प्रतिशत (%)	शाखाएं (संख्या में)
2015	60.3	5.8	87,000
2016	65.7	6.1	88,000
2017	70.4	6.0	89,500
2018	72.0	5.7	91,000
2019	74.5	5.3	93,000
2020	78.2	4.9	95,000

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

2015 से 2020 के बीच भारत के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास देखा गया, विशेषकर ऋण वितरण, शाखाओं के विस्तार और एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों) में कमी के रूप में। वर्ष 2015 में सहकारी बैंकों द्वारा कुल ₹60.3 हजार करोड़ का क्रेडिट वितरण किया गया, जो अगले वर्षों में लगातार बढ़ता गया और 2020 तक यह ₹78.2 हजार करोड़ तक पहुँच गया, जो ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सहकारी वित्तीय सेवाओं की मांग और पहुँच में वृद्धि को दर्शाता है। इस अवधि में सहकारी बैंकों ने अपनी सेवाओं का विस्तार करते हुए 87,000 शाखाओं से बढ़ाकर 95,000 शाखाएँ स्थापित कीं, जिससे देश के दूरदराज़ क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाएँ सुलभ हो सकीं। यह विस्तार सरकार की वित्तीय समावेशन योजनाओं, जैसे जनधन योजना और DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) को लागू करने में भी सहायक रहा। एनपीए प्रतिशत, जो बैंकों के जोखिम और ऋण वसूली की स्थिति को दर्शाता है, 2015 में 5.8% था जो 2020 तक घटकर 4.9% हो गया। यह गिरावट सहकारी बैंकों की सुधारात्मक नीतियों, क्रेडिट मूल्यांकन की प्रक्रियाओं में सुधार, और डिजिटल भुगतान प्रणालियों को अपनाने के कारण संभव हुई। इस दौरान बैंकों ने कोर बैंकिंग सिस्टम (CBS), मोबाइल बैंकिंग, और कस्टमर रिव्यू मैकेनिज्म जैसे डिजिटल सुधारों को अपनाया, जिससे ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता में बढ़ोतरी हुई। कुल मिलाकर, यह अवधि सहकारी बैंकिंग प्रणाली के स्थायित्व, विस्तार और सुधार की दृष्टि से अत्यंत सकारात्मक रही, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और छोटे किसानों, व्यापारियों एवं महिलाओं को औपचारिक ऋण प्रणाली से जोड़ने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग में सहकारी भागीदारी

साझेदार संगठन	सहयोग प्रारंभ वर्ष	प्रमुख योगदान
ICA	1995	नीतिगत मार्गदर्शन और नेटवर्किंग
FAO	2001	खाद्य सुरक्षा परियोजनाएं
IFAD	2005	कृषि ऋण और तकनीकी सहयोग
ILO	2010	श्रम अधिकार और सहकारी प्रशिक्षण

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

UNDP	2012	डिजिटल और सतत विकास परियोजनाएं

भारत में सहकारी आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ बनाने में विभिन्न वैश्विक संगठनों का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इन सहयोगों ने न केवल सहकारी सिद्धांतों के प्रसार को बढ़ावा दिया, बल्कि भारत की सहकारी संस्थाओं को वैश्विक मानकों और तकनीकी दक्षताओं से जोड़ने का मार्ग भी प्रशस्त किया। 1995 में अंतरराष्ट्रीय सहकारी संघ (ICA) के साथ भारत का सहयोग प्रारंभ हुआ, जिसने नीतिगत मार्गदर्शन, वैश्विक नेटवर्किंग, और सदस्य देशों के बीच अनुभवों के आदान-प्रदान को सशक्त बनाया। इसके माध्यम से भारत की सहकारी समितियाँ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, प्रशिक्षणों और शोध गतिविधियों में भाग लेने लगीं, जिससे उनकी दृष्टि और कार्यप्रणाली का विस्तार हुआ। खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने 2001 से सहयोग प्रारंभ किया, जिसका मुख्य फोकस खाद्य सुरक्षा परियोजनाओं पर रहा, विशेष रूप से किसानों की उत्पादन क्षमता, फसल विविधीकरण और जलवायु-सहिष्णु कृषि के क्षेत्र में। अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) के साथ 2005 में हुए सहयोग के तहत सहकारी समितियों को कृषि ऋण, माइक्रोफाइनेंस और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया गया, जिससे ग्रामीण किसानों की वित्तीय पहुँच में उल्लेखनीय सुधार आया। 2010 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के साथ सहयोग ने सहकारी कार्यस्थलों में श्रमिकों के अधिकार, लैंगिक समानता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद की, जबकि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने 2012 से डिजिटल समावेशन, ई-गवर्नेंस और सतत विकास परियोजनाओं में सहायता दी। UNDP की तकनीकी सहायता से सहकारी समितियों में डेटा प्रबंधन, ट्रांसपेरेंसी और मोबाइल-बेस्ड सेवाओं की शुरुआत हुई, जिससे उनका संचालन अधिक प्रभावी हुआ। इन अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों ने भारतीय सहकारिता प्रणाली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, तकनीकी रूप से सक्षम और नीति-समर्थ बनाने में अभूतपूर्व योगदान दिया है।

दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध उत्पादन

वर्ष	**दुग्ध उत्पादन (मिलियन टन)**	**सहकारी योगदान (%)**
2000	78	42
2005	92	47

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

2010	116	50
2015	146	53
2020	198	58
2024	220	60

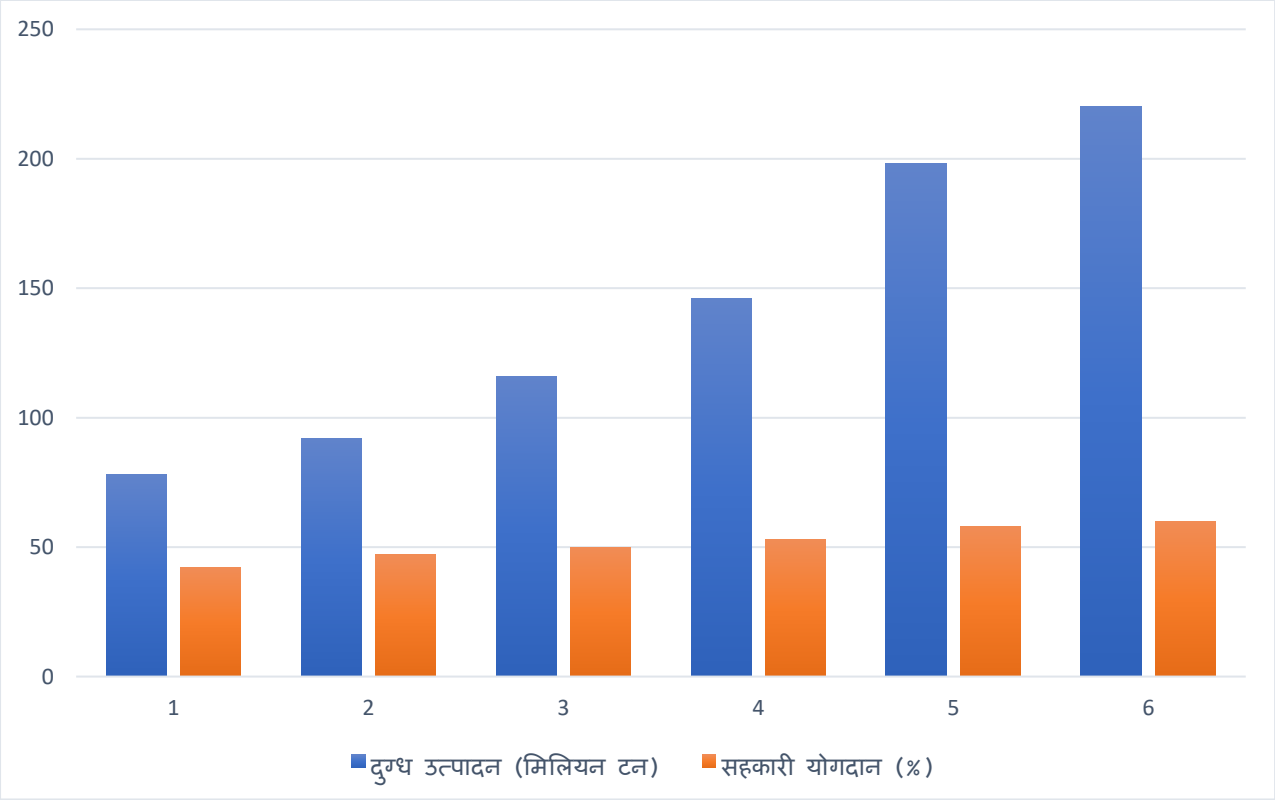

भारत में दुग्ध सहकारी समितियों ने देश को विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2000 से लेकर 2024 तक के आँकड़े यह दर्शाते हैं कि दुग्ध उत्पादन में न केवल तीव्र वृद्धि हुई है, बल्कि सहकारी समितियों का योगदान भी लगातार बढ़ा है। वर्ष 2000 में भारत का कुल दुग्ध उत्पादन 78 मिलियन टन था, जिसमें सहकारी समितियों का योगदान 42% था। यह वह समय था जब अमूल मॉडल और अन्य राज्य स्तरीय दुग्ध सहकारी समितियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत हो रही थीं। 2005 तक यह उत्पादन बढ़कर 92 मिलियन टन हो गया और सहकारी योगदान 47% तक पहुँच गया, जो यह दर्शाता है कि दुग्ध संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन में सहकारी संरचनाएँ अधिक प्रभावी बन रही थीं। 2010 में उत्पादन 116 मिलियन टन तक पहुँचा और सहकारी भागीदारी 50% को पार कर

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

गई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि ग्रामीण पशुपालक और छोटे किसान इन संस्थाओं से अधिक मात्रा में जुड़ रहे थे। 2015 तक यह आँकड़ा 146 मिलियन टन और 53% योगदान तक पहुँचा, और सरकार द्वारा "राष्ट्रीय डेयरी योजना" तथा "डेयरी सहकारिता डिजिटलकरण योजना" जैसे अभियानों से इसे और गति मिली। 2020 तक उत्पादन 198 मिलियन टन और सहकारी योगदान 58% तक पहुँच गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि सहकारी मॉडल ने दुग्ध क्षेत्र में समावेशी विकास और महिलाओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया। वर्ष 2024 के अनुमान के अनुसार, कुल उत्पादन 220 मिलियन टन होने की संभावना है जिसमें 60% योगदान सहकारी समितियों का होगा। यह वृद्धि केवल आँकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण स्तर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का भी एक सशक्त संकेत है।

सहकारी संस्थाओं के माध्यम से रोजगार सृजन

क्षेत्र	**प्रत्यक्ष रोजगार (लाख में)**	**परोक्ष रोजगार (लाख में)**
कृषि	9.8	12.5
दुग्ध	6.4	7.6
उपभोक्ता स्टोर	2.3	3.0
बैंकिंग	4.1	5.0
शिल्प/हस्तशिल्प	1.7	2.1

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

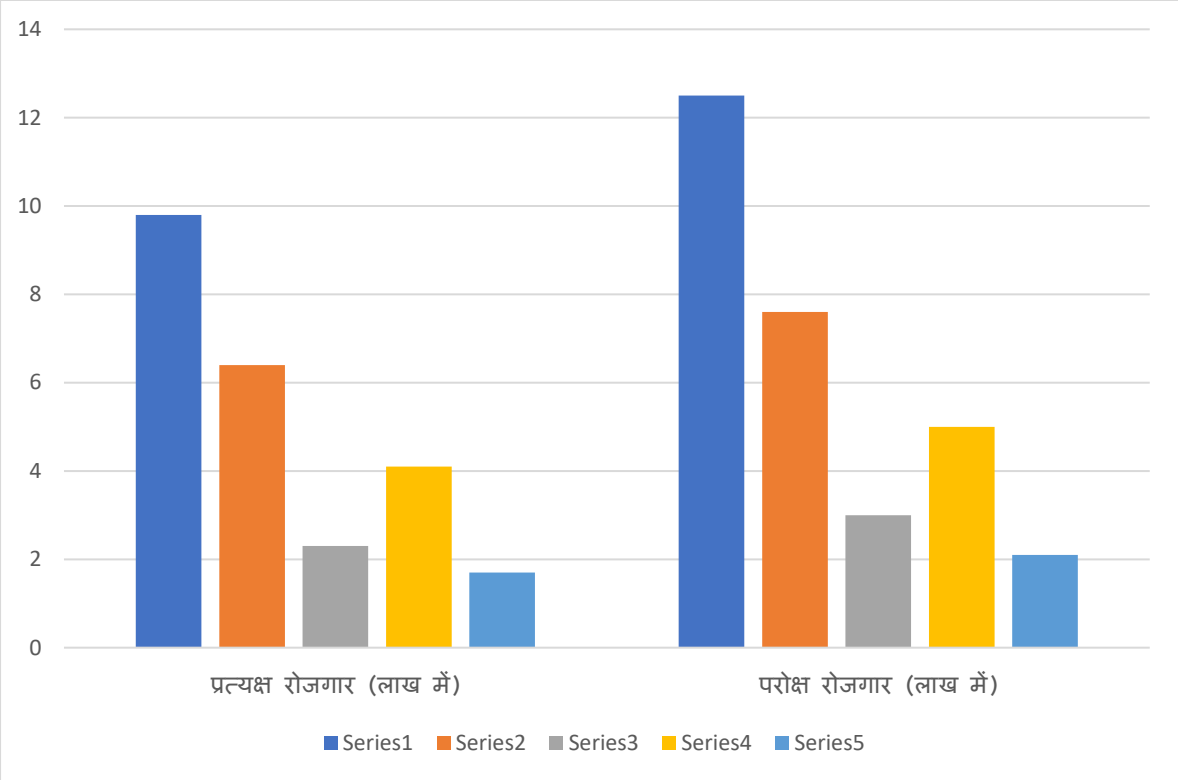

भारत में सहकारी संस्थाओं ने रोजगार सृजन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है, विशेषतः ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में जहाँ पारंपरिक रोजगार के अवसर सीमित होते हैं। सहकारिता प्रणाली ने न केवल आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया बल्कि सामाजिक समावेशन और स्थानीय विकास को भी गति दी। विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं की सक्रियता से प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार के रोजगार उत्पन्न हुए हैं। कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक 9.8 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है जबकि 12.5 लाख लोग परोक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं, जो कृषि उत्पादों की खरीद, भंडारण, विपणन और वितरण में कार्यरत हैं। इसी प्रकार दुग्ध सहकारी समितियों ने ग्रामीण महिलाओं और पशुपालकों को जोड़ते हुए 6.4 लाख प्रत्यक्ष और 7.6 लाख परोक्ष रोजगार उपलब्ध कराए हैं, जिसमें दुग्ध संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित कार्य शामिल हैं। उपभोक्ता सहकारी स्टोर, जो राशन, खाद्य पदार्थ, और आवश्यक वस्तुएँ सस्ती दरों पर उपलब्ध कराते हैं, ने 2.3 लाख प्रत्यक्ष और 3 लाख परोक्ष रोजगार उत्पन्न किए हैं। बैंकिंग क्षेत्र में सहकारी बैंकों और क्रेडिट सोसाइटियों के माध्यम से 4.1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से तथा 5 लाख लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है, जो वित्तीय समावेशन और ग्रामीण ऋण प्रणाली को सशक्त बनाता है। वहीं शिल्प और हस्तशिल्प सहकारी समितियाँ, विशेष रूप से महिला और

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

जनजातीय समुदायों के लिए, 1.7 लाख प्रत्यक्ष और 2.1 लाख परोक्ष रोजगार का साधन बनी हैं। इस प्रकार सहकारी संस्थाएँ केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये रोजगार सृजन, उद्यमिता को बढ़ावा देने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की एक मजबूत कड़ी बन चुकी हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार हैं।

निष्कर्ष

भारत में सहकारी आंदोलन और राजनीति का संबंध ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत गहरा है। प्रारंभ में यह आंदोलन किसानों, मजदूरों और वंचित वर्गों के आर्थिक उत्थान तथा सामूहिक सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू हुआ था, परंतु समय के साथ यह ग्रामीण राजनीति और सत्ता संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। वैश्वीकरण ने सहकारी आंदोलन की दिशा और परिणामों को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। एक ओर, वैश्वीकरण ने सहकारी समितियों को वैश्विक बाजार तक पहुँच, निर्यात की संभावनाएँ, नई तकनीकों का उपयोग, प्रबंधन सुधार और वित्तीय संसाधनों तक पहुँच का अवसर प्रदान किया, जिससे यह आंदोलन आधुनिक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप ढल सका। दूसरी ओर, निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की चुनौती, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी ने इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाए। महाराष्ट्र की चीनी सहकारी समितियों और गुजरात की डेयरी सहकारिताओं जैसे उदाहरण बताते हैं कि कैसे सहकारिता राजनीति और सत्ता का आधार बनी, परंतु साथ ही ग्रामीण विकास और लोकतांत्रिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया। इस प्रकार, भारत में सहकारी आंदोलन आज दोहरी स्थिति में है—यह विकास, आत्मनिर्भरता और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का साधन भी है, और राजनीतिकरण तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दबाव का शिकार भी। आवश्यकता इस बात की है कि सहकारी आंदोलन को राजनीति के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त कर उसकी आत्मा—सहयोग, समानता और सामूहिकता—को सुदृढ़ किया जाए, तभी यह वैश्वीकरण के दौर में भारतीय समाज और लोकतंत्र के लिए एक स्थायी और सशक्त आधार बन सकेगा।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

संदर्भ

शेफ़र, आर. के. (2003). वैश्वीकरण को समझना: राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिवर्तनों के सामाजिक परिणाम. रोमन एंड लिटलफील्ड।

स्टिग्लिट्ज, जे. ई. (2002). वैश्वीकरण और इसके असंतोष। डब्ल्यू. डब्ल्यू. नॉर्टन एंड कंपनी।

हेइरॉन्ग, वाई., और यीयुआन, सी. (2016). चीन में ग्रामीण सहकारी आंदोलन पर बहस: अतीत और वर्तमान. समकालीन चीन की ग्रामीण राजनीति में (पृष्ठ 49-75)। रूटलेज।

दास, बी., पलई, एन. के., एवं दास, के. (2006). *वैश्वीकरण की स्थिति में भारत में सहकारी आंदोलन की समस्याएँ एवं संभावनाएँ.* चौदहवाँ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक इतिहास सम्मेलन, हेलसिंकी।

सिंह, एस. के. (2016). *मुक्त बाजार में भारत के सहकारी क्षेत्र की समस्याएँ एवं संभावनाएँ. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी.* https://doi.org/10.25215/0304.073

सैनी, एस. (2020?). *भारत में सहकारी क्षेत्रों की समस्याएँ और चुनौतियाँ.* एआईएसईसीटी विश्वविद्यालय, भोपाल।

जेटिर. (2023). *भारत में सहकारी आंदोलन का इतिहास और विकास: एक विवेचन. जेटिर जर्नल.*

मीडिया भारती. (तिथि अज्ञात). *सहायता और समृद्धि के मूल्यों को सहेजता है भारत का सहकारी आंदोलन.* मीडिया भारती।

प्रेस सूचना ब्यूरो. (14 नवम्बर 2024). *भारत का सहकारी आंदोलन: समावेशी विकास को बढ़ावा.* प्रेस सूचना ब्यूरो।

दृष्टि क्यूट. (26 नवम्बर 2024). *वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024: भारत के सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाना.* दृष्टि क्यूट।

दृष्टि आईएएस. (2021). *भारत में सहकारी आंदोलन.* दृष्टि आईएएस।